स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) विभिन्न विदेशी अभिकरणों से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए वित्तीय, सामग्री तथा तकनीकी सहायता प्राप्त की जाती है। पिछले तीन वर्ष के दौरान इन अभिकरणों से प्राप्त विदेशी सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)।

(ग) परिवार कल्याण से संबंधित परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता दी जाती है जो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अनुरूप हैं।

(घ) और (ङ) में प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय सहायता

क्र०सं०	धन दाता अभिकरण का नाम	1993-94	1994-95	(करोड़ रुपयों में) 1995-96
1.	विश्व बैंक	240.71	309.36	312.25
2.	यू०एन०एफ०पी०ए०	21.89	37.13	42.00
3.	यू०एन०आई०सी०ई०एफ०	35.35	65.35	39.99
4.	यू०एस०ए०आई०डी०	13.94	21.29	22.28
5.	विश्व स्वास्थ्य संगठन	4.44	1.69	10.94
6.	ओ०डी०ए०	6.23	14.48	10.52
7.	डानिडा	6.00	6.97	1.20
8.	नोराड	2.67	0.16	—

Discussions Held by President of World Bank with RBI Governor and Chairman, SEBI

1852. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that President World Bank had discussions with the Governor of Reserve Bank of India and the Chairman, Security and Exchange Board of India on 15th October, 1996;

(b) if so, details of the issues discussed; and

(c) the decisions, if any taken on the issues?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes Sir. The Governor Reserve Bank of India, and the Chairman, Securities and Exchange Board of India alongwith the heads of the Financial Institutions and Banks met the President of the World Bank on October 15, 1996.

(b) and (c) During the meeting the general state of the economy, including the state of the capital markets was discussed. However, no decisions were taken.

Share of Delhi in the Central Taxes

1853. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the share of Delhi in the Central taxes and how is that amount calculated, giving the details of the formula/basis thereof;

(b) when was that formula/basis arrived at;

(c) how much amount does it work out as per the existing formula/basis and how much money has been released to the Delhi Government in the last three years and during 1996;

(d) whether the Delhi Government has taken any exception to the indifferent attitude of Government towards their finances; and

(e) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (e) Under the Constitution the proceeds of some of the Central Taxes and Duties are shared with the States only. Therefore the Union Territories (whether with or without Legislature) are not entitled and have not been paid any share in Central Taxes and Duties.

आवश्यक वस्तुओं का थोक बिक्री मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

1854. **श्री गोविन्दराम मिरीः**
श्रीमती मालती शर्माः

क्या वित्त मंत्री 26 नवम्बर, 1996 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 462 और तारांकित प्रश्न 77 को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक बिक्री मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ब्यौरा क्या है;

(ख) मूल्य सूचकांक में लगातार वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने मूल्यों में वृद्धि और मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) पिछले छह महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी०आई०) तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी०पी०आई०) नीचे सूचीबद्ध हैः—

महीना	थोक मूल्य सूचकांक (1981-82=100)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=100)
मई, 1996	305.5	326
जून	313.0	332
जुलाई	318.0	336
अगस्त	323.1	339
सितम्बर	327.4	342
अक्टूबर	330.2	उ०न०
16 नवम्बर	334.7	उ०न०

(ख) मूल्यों में वृद्धि जो पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 96) में संतुलित बनी रही थी, में पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगभग 18 प्रतिशत की औसत वृद्धि के बाद जुलाई से उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दिखाई देनी आरम्भ हुई। यह उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति कोयले की कीमतों में संशोधन और खाद्यान्नों की कीमतों विशेषकर चावल और गेहूं की कीमतों में तीव्र वृद्धि द्वारा और अधिक प्रबल हो गई। 1995-96 में खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट के कारण आपूर्ति में कुछ कमी आई, विशेष रूप से गेहूं के मामले में जिसके परिणामस्वरूप इसकी कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई।

(ग) सरकार ने मूल्यों और मुद्रास्फीति में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में उपाय किए हैं, जिन में ये शामिल हैं:—

(1) भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और गेहूं की खुले बाजार में बिक्री को जारी रखना।

(2) चीनी, खाद्य तेलों, दालों तथा कम वसा वाले दूध पाउडर जैसी चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के लिए शून्य या घटे शुल्कों पर ओ०जी०एल० आयात नीति को जारी रखना।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए